Government Budget and the Economy

We introduced the government in chapter one as denoting the state. We stated that apart from the private sector, there is the government which plays a very important role. An economy in which there is both the private sector and the Government is known as a mixed economy. There are many ways in which the government influences economic life. In this chapter, we will limit ourselves to the functions which are carried on through the government budget.

प्रथम अध्याय में हमने सरकार का परिचय राज्य के रूप में करवाया था। हमने कहा था कि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त, सरकार होती है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों हो, भिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। एसे बहुत से तरीके हैं जिनसे सरकार जीवन के आर्थिक पहलू को प्रभावित करती है। इस अध्याय में, हम केवल उन कार्यों की व्याख्या करेंगे जो सरकारी बजट के माध्यम से किए जाते हैं।

Government Budget and the Economy

In section 5.1 we present the components of the government budget to bring out the sources of government revenue and avenues of government spending. In section 5.2 we discuss the topic of balanced, surplus or deficit budget to account for the difference between expenditures and revenue collection. It specifically deals with the meaning of different kinds of budget deficits, their implications and the measures to contain them.

खंड 5.1 में हम सरकारी बजट के अवयवों को प्रस्तुत करेंगे ताकि सरकारी आगम के स्रोतों तथा सरकारी व्यय की विधियों को समझाया जा सके। खंड 5. 2 में, हम संतुलित, अधिक्य तथा घाटे के बजट की व्याख्या करेंगे ताकि व्यय तथा कुल आगम में अंतर को स्पष्ट किया जा सके। हम यहां विशेष रूप से बजट के घाटों के प्रकार, उनके निहितार्थ तथा इन्हें नियंत्रित रखने के उपायों की व्याख्या करेंगे।

Government Budget and the Economy

Box. 5.1 deals with fiscal policy and a simple description of the multiplier. The role the government plays has implications for its deficits which further affect its debtwhat the government owes. The chapter concludes with an analysis of the debt issue.

बॉक्स 5.1 राजकोषीय नीति तथा गुणक की सरल व्याख्या करता है। सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका का इसके घाटों के लिए भी निहितार्थ हैं जो आगे सरकारी ऋण को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय सार्वजनिक ऋण के विश्लेषण के साथ समाप्त होता है।

Government Budget and the Economy

GOVERNMENT BUDGET – MEANING AND ITS COMPONENTS

There is a constitutional requirement in India (Article 112) to present before the Parliament a statement of estimated receipts and expenditures of the government in respect of every financial year which runs from 1 April to 31 March. This 'Annual Financial Statement' constitutes the main budget document of the government.

सरकारी बजट–अर्थ तथा इसके अवयव

1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत में (संवैधानिक 112) संवैधानिक आवश्यकता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' सरकार के मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है।

Government Budget and the Economy

Although the budget document relates to the receipts and expenditure of the government for a particular financial year, the impact of it will be there in subsequent years. There is a need therefore to have two accounts- those that relate to the current financial year only are included in the revenue account (also called revenue budget) and those that concern the assets and liabilities of the government into the capital account (also called capital budget).

हालांकि बजट दस्तावेज रसीदों से संबंधित है और एक विशेष वित्तीय के लिए सरकार का खर्च वर्ष, इसका प्रभाव बाद के वर्षों में होगा। इसलिए दो खातों की जरूरत है- जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं केवल में शामिल हैं राजस्व खाता (जिसे राजस्व बजट भी कहा जाता है) और वे सरकार की संपत्ति और देनदारियों में चिंता पूंजी खाता (जिसे पूंजी बजट भी कहा जाता है)।

Government Budget and the Economy

Objectives of Government Budget

The government plays a very important role in increasing the welfare of the people. In order to do that the government intervenes in the economy in the following ways.

सरकारी बजट के उद्देश्य

सरकार जन-कल्याण बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए, सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है।

Government Budget and the Economy

Allocation Function of Government Budget

Government provides certain goods and services which cannot be provided by the market mechanism i.e. by exchange between individual consumers and producers. Examples of such goods are national defence, roads, government administration etc. which are referred to as public goods.

सरकारी बजट का आबंटन कार्य

सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है, जिन्हें बाजार-तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता अर्थात् उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं—राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें तथा सरकारी प्रशासन, जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएँ कहा जाता है।

Two, in case of private goods anyone who does not pay for the goods can be excluded from enjoying its benefits. If you do not buy a ticket, you will not be allowed to watch a movie at a local cinema hall. However, in case of public goods, there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefits of the good. That is why public goods are called non-excludable. Even if some users do not pay, it is difficult and sometimes impossible to collect fees for the public good. These nonpaying users are known as 'free-riders'.

दूसरे, निजी वस्तुओं के सन्दर्भ में, जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता, उसे इनका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है। यदि आप टिकट न खरीदें, तो आपको सिनेमा घर में फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के सन्दर्भ में, किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य (कारगर) तरीका नहीं है। इसीलिए सार्वजनिक वस्तुओं को गैर–अपवर्जनीय कहा जाता है। यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं भी करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं, अपितु बहुत बार असंभव हो जाता है। इन भुगतान दिए बिना उपयोग करने वालों को मुफ्तखोर कहा जाता है।

Government Budget and the Economy

There is, however, a difference between public provision and public production. Public provision means that they are financed through the budget and can be used without any direct payment. Public goods may be produced by the government or the private sector. When goods are produced directly by the government it is called public production.

सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अन्तर होता है। वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्तपोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इनका उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है। जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है, तो इसे सार्वजनिक उत्पादन कहा जाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आबंटन कायं कहा जाता है।

Government Budget and the Economy

Redistribution Function of Government Budget

From chapter two we know that the total national income of the country goes to either the private sector, that is, firms and households (known as private income) or the government (known as public income). Out of private income, what finally reaches the households is known as personal income and the amount that can be spent is the personal disposable income. The government sector affects the personal disposable income of households by making transfers and collecting taxes.

सरकारी बजट का पुनः आबंटन कार्य

अध्याय दो से हमें पता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात् फर्मो तथा घरेलू क्षेत्र की ओर (जिसे निजी आय कहा जाता है) या सरकार की ओर (जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है)। निजी आय में से जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुँचता है, उसे वैयक्तिक आय कहा जाता है, तथा उसमें से जिस भाग को खर्च किया जा सकता है, वह भाग प्रयोज्य आय कहलाता है। सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है।

Government Budget and the Economy

Stabilisation Function of Government Budget

The government may need to correct fluctuations in income and employment. The overall level of employment and prices in the economy depends upon the level of aggregate demand which depends on the spending decisions of millions of private economic agents apart from the government. These decisions, in turn, depend on many factors such as income and credit availability.

सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य

सरकार को आय तथा रोजगार में उतार-चढ़ाव को भी कम करना होता है। अर्थव्यवस्था में, रोजगार का तथा कीमतों का स्तर कुल माँग पर निर्भर करता है तथा कुल माँग, सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों-करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। ये निर्णय भी कई कारकों, जैसे आय तथा साख की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

Government Budget and the Economy

The intervention of the government whether to expand demand or reduce it constitutes the stabilisation function.

सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह माँग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है।

Government Budget and the Economy

Classification of Receipts

Revenue Receipts: **Revenue receipts are those receipts that do not lead to a claim on the government. They are therefore termed non-redeemable. They are divided into tax and non-tax revenues. Tax revenues, an important component of revenue receipts, have for long been divided into direct taxes (personal income tax) and firms (corporation tax), and indirect taxes like excise taxes (duties levied on goods produced within the country), customs duties (taxes imposed on goods imported into and exported out of India) and service tax1 . Other direct taxes like wealth tax, gift tax and estate duty (now abolished) have never brought in large amount of revenue and thus have been referred to as 'paper taxes'.**

प्राप्तियों का वर्गीकरण

राजस्व प्राप्तियां: राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। अत: इन्हें गैर-प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर तथा गैर-कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर-राजस्व, जो कि राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है, को काफी समय से प्रत्यक्ष करों (वैयक्तिक आय कर तथा फर्मों के लिए निगम कर) तथा अप्रत्यक्ष कर, जैसे उत्पादन कर (देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर), सीमाशुल्क (आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर) तथा सेवा कर।

Government Budget and the Economy

Non-tax revenue of the central government mainly consists of interest receipts on account of loans by the central government, dividends and profits on investments made by the government, fees and other receipts for services rendered by the government.

केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां होती हैं केंद्र सरकार द्वारा ऋण के आधार पर लाभांश और मुनाफे पर प्रदत्त सेवाओं के लिए सरकार द्वारा किए गए निवेश, शुल्क और अन्य रसीदें सरकार की ओर से।

The estimates of revenue receipts take into account the effects of tax proposals made in the Finance Bill .

राजस्व प्राप्तियों के अनुमान कर प्रस्तावों के प्रभावों को ध्यान में रखते हैं वित्त बिल 2 में बनाया गया |

Government Budget and the Economy

Capital Receipts: **The government also receives money by way of loans or from the sale of its assets. Loans will have to be returned to the agencies from which they have been borrowed. Thus they create liability. Sale of government assets, like sale of shares in Public Sector Undertakings (PSUs) which is referred to as PSU disinvestment, reduce the total amount of financial assets of the government. All those receipts of the government which create liability or reduce financial assets are termed as capital receipts.**

पूँजीगत प्राप्तियां: सरकार को ऋणों के रूप में भी धनराशि मिलती है या संपत्ति को बेचने से भी। जिन संस्थाओं से ऋण लिया गया है, उन्हें इसकी अदायगी भी करनी होती है। अत: ऋणों से देयता पैदा होती है। इसी प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने शेयरों (अंशों) की बिक्री, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश भी कहते हैं) से सरकार की वित्तीय संपत्तियों की मात्रा कम हो जाती है। सरकार की एसी सभी प्राप्तियां, जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियों कम हों, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं।

Government Budget and the Economy

When government takes fresh loans it will mean that in future these loans will have to be returned and interest will have to be paid on these loans. Similarly, when government sells an asset, then it means that in future its earnings from that asset, will disappear. Thus, these receipts can be debt creating or non-debt creating.

जब सरकार नय ऋण लेती है तो इस का अर्थ यह है कि इस ऋण को लौटाया जायगा और इन पर बयान दिया जायगा। इसी भांति जब सरकार किसी आस्ति को बेचती है तो इस का अर्थ है कि भविष्य से इससे आय समाप्त हो जायगी। इस प्रकार, य प्राप्तियां ऋण–उत्पादक या गैर–ऋण उत्पादक हो सकती हैं।

Government Budget and the Economy

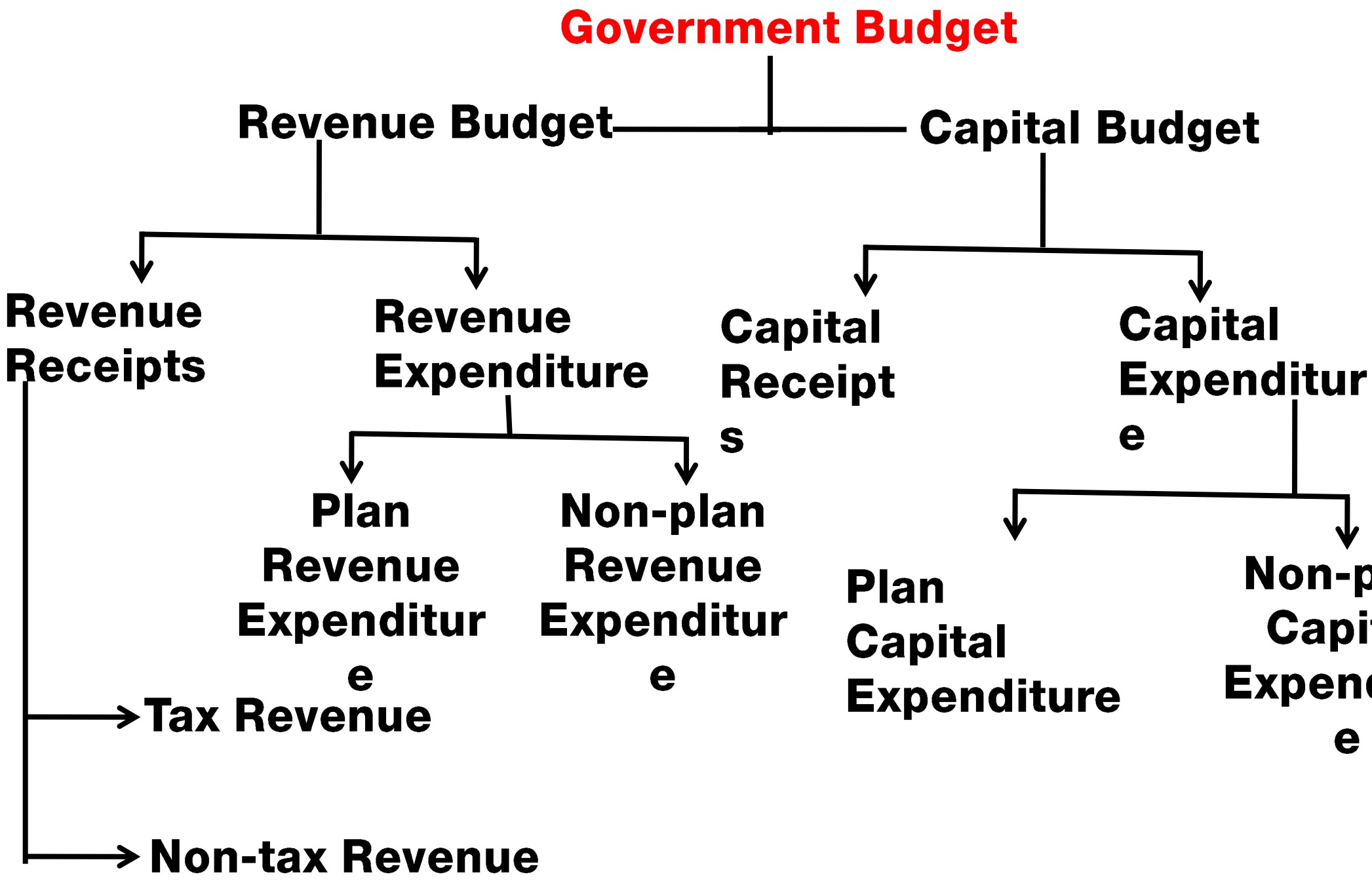

Government Budget and the Economy

Classification of Expenditure

Revenue Expenditure

Revenue Expenditure is expenditure incurred for purposes other than the creation of physical or financial assets of the central government. It relates to those expenses incurred for the normal functioning of the government departments and various services, interest payments on debt incurred by the government, and grants given to state governments and other parties (even though some of the grants may be meant for creation of assets).

पूँजीगत लेखा

राजस्व व्यय: राजस्व व्यय केन्द्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदानों से परिसंपत्तियों का सृजन भी हो सकता है) आदि पर किय गए व्यय से होता है।

Government Budget and the Economy

Budget documents classify total expenditure into plan and non-plan expenditure3 . This is shown in item 6 on Table 5.1 within revenue expenditure, a distinction is made between plan and non-plan. According to this classification, plan revenue expenditure relates to central Plans (the Five-Year Plans) and central assistance for State and Union Territory plans. Non-plan expenditure, the more important component of revenue expenditure, covers a vast range of general, economic and social services of the government.

बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय को योजनागत और गैर–योजनागत व्यय मदों में बाँटा जाता है। योजनागत राजस्वगत व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं (पंचवर्षीय योजनाओं) और राज्यों तथा संघ–शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से है। गैर–योजनागत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं।

Government Budget and the Economy

The main items of non-plan expenditure are interest payments, defence services, subsidies, salaries and pensions.

गैर–योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएँ, उपदान, वेतन और पेंशन आते हैं।

Interest payments on market loans, external loans and from various reserve funds constitute the single largest component of non-plan revenue expenditure. Defence expenditure, is committed expenditure in the sense that given the national security concerns, there exists little scope for drastic reduction. Subsidies are an important policy instrument which aim at increasing welfare.

बाज़ार ऋणों, बाह्य ऋणों और विविध आरक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी गैर–योजनागत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक होता है। प्रतिरक्षा व्यय गैर–योजनागत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है और इस अर्थ में यह प्रतिबद्ध व्यय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस मद में अधिक कटौती का क्षेत्र अत्यल्प है। उपदान एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है, जिसका उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना है।

Government Budget and the Economy

Capital Expenditure

There are expenditures of the government which result in creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities. This includes expenditure on the acquisition of land, building, machinery, equipment, investment in shares, and loans and advances by the central government to state and union territory governments, PSUs and other parties. Capital expenditure is also categorised as plan and non-plan in the budget documents.

पूँजीगत व्यय:

य सरकार के वे व्यय हैं जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है। पूँजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ–शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किय गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। पूँजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर–योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

Government Budget and the Economy

Plan capital expenditure, like its revenue counterpart, relates to central plan and central assistance for state and union territory plans. Non-plan capital expenditure covers various general, social and economic services provided by the government.

इस वर्गीकरण के अनुसार, योजनागत पूँजीगत व्यय का संबंध राजस्व-व्यय के समान, केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ-शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। गैर-योजनागत पूँजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल होते हैं।

Government Budget and the Economy

Along with the budget, three policy statements are mandated by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA)4 . The Medium-term Fiscal Policy Statement sets a three year rolling target for specific fiscal indicators and examines whether revenue expenditure can be financed through revenue receipts on a sustainable basis and how productively capital receipts including market borrowings are being utilised.

वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 20034 के द्वारा बजट के साथ तीन नीतिगत विवरणों का होना अनिवायं है। मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण में विशिष्ट वित्तीय सूचकों के लिए तीन वर्षीय चल लक्ष्य रहता है, जो इस बात का परीक्षण करता है कि क्या धारणीय आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय किया जा सकता है और बाज़ार ऋण–ग्रहण सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग कितनी उत्पादकता के रूप में किया जा रहा है।

Government Budget and the Economy

BALANCED, SURPLUS AND DEFICIT BUDGET

The government may spend an amount equal to the revenue it collects. This is known as a balanced budget. If it needs to incur higher expenditure, it will have to raise the amount through taxes in order to keep the budget balanced. When tax collection exceeds the required expenditure, the budget is said to be in surplus. However, the most common feature is the situation when expenditure exceeds revenue. This is when the government runs a budget deficit.

संतुलित, अधिशेष एवं घाटा बजट

सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है। इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है, तो बजट को संतुलित रखने के लिय, करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है, तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। हालांकि मुख्यत: एसी भी स्थिति होती है जब व्यय राजस्व से अधिक हो। यह तब होता है जब सरकार घाटा वाली बजट को चलाती है।

Government Budget and the Economy

Measures of Government Deficit

When a government spends more than it collects by way of revenue, it incurs a budget deficit6 . There are various measures that capture government deficit and they have their own implications for the economy.

Revenue Deficit: The revenue deficit refers to the excess of government's revenue expenditure over revenue receipts

सरकारी घाटे की माप

जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, तो इस स्थिति को बजटीय घाटा6 कहते हैं। इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।

राजस्व घाटा: राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां

➢**Revenue deficit = Revenue expenditure – Revenue receipts**

Government Budget and the Economy

1. **Revenue Receipts (a+b)**
   - **(a) Tax revenue (net of states' share)**
   - **(b) Non-tax revenue**
2. **Revenue Expenditure of which**
   - **(a) Interest payments**
   - **(b) Major subsidies**
   - **(c) Defence expenditure**
3. **Revenue Deficit (2–1)**

1. राजस्व प्राप्तियां (a + b)
   - (a) कर राजस्व (राज्यों के निवल अंश)
   - (b) गैर–कर राजस्व
2. राजस्व खर्च जिसका
   - (a)- राजस्व खर्च जिसका
   - (b) प्रमुख उपदान
   - (c) रक्षा व्यय
3. राजस्व घाटा (2 – 1)

Government Budget and the Economy

4. Capital Receipts (a+b+c) of which

(a) Recovery of loans

(b) Other receipts (mainly PSU1 disinvestment)

(c) Borrowings and other liabilities

5. Capital Expenditure

6. Non-debt Receipts [1+4(a)+4(b)]

7. Total Expenditure [2+5=7(a)+7(b)]

(a) Plan expenditure –

(b) Non-plan expenditure –

4. पूँजीगत प्राप्तियां (a+b+c) जिसका
   (a) ऋण वसूली
   (b) अन्य प्राप्तियां(मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का विनिवेश)
   (c) ऋण ग्रहण एवं अन्य दायित्व

5- पूँजीगत व्यय

6- गैर–ऋण प्राप्तियां [1 + 4(a) + 4(b)]

7- कुल व्यय [2 + 5 = 7(a) + 7(b)]
   (a)योजनागत व्यय
   (b) गैर–योजनागत व्यय

Government Budget and the Economy

8. Fiscal deficit [7-1-4(a)-4(b)]

9. Primary Deficit [8–2(a)]

8- राजकोषीय घाटा [7 – 1 – 4(a) – 4(b)]

9- प्राथमिक घाटा [8 – 2 = (a)]

Government Budget and the Economy

Fiscal Deficit: Fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding borrowing Gross fiscal deficit = Total expenditure – (Revenue receipts + Non-debt creating capital receipts)

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण–ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + गैर–ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियां)

Non-debt creating capital receipts are those receipts which are not borrowings and, therefore, do not give rise to debt. Examples are recovery of loans and the proceeds from the sale of PSUs. From Table 5.1 we can see that non-debt creating capital receipts equals 8.8 per cent of GDP, obtained by subtracting, borrowing and other liabilities from total capital receipts [1+4(a)+4(b)]. The fiscal deficit, therefore turn out to be 3.4 per cent of GDP.

गैर–ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियां एसी प्राप्तियां हैं, जो ऋण–ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसीलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती है। इसके उदाहरण हैं–ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि। तालिका 5.1 में हम देखते हैं कि गैर–ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद के 8.8 प्रतिशत के बराबर है। यह कुल पूँजीगत प्राप्तियों में से उधार और अन्य दायित्वों को घटाकर [1+4(a)+4(b)] प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत प्रतीत होता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है।

Government Budget and the Economy

The fiscal deficit will have to be financed through borrowing. Thus, it indicates the total borrowing requirements of the government from all sources. From the financing side

Gross fiscal deficit = Net borrowing at home + Borrowing from RBI + Borrowing from abroad

राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण–ग्रहण के द्वारा ही किया जायेगा। अत: इससे सभी स्त्रोतों से सरकार के ऋण–ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है। वित्तीय पक्ष से,

सकल राजकोषीय घाटा = निवल घरेलू ऋण–ग्रहण + भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण–ग्रहण + विदेशों से ऋण–ग्रहण।

Government Budget and the Economy

The gross fiscal deficit is a key variable in judging the financial health of the public sector and the stability of the economy. From the way gross fiscal deficit is measured as given above, it can be seen that revenue deficit is a part of fiscal deficit (Fiscal Deficit = Revenue Deficit + Capital Expenditure - non-debt creating capital receipts). A large share of revenue deficit in fiscal deficit indicated that a large part of borrowing is being used to meet its consumption expenditure needs rather than investment.

इस प्रकार सकल राजकोषीय घाटा को मापा जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा का एक भाग है (राजकोषीय घाटा = राजस्व घाटा + पूँजीगत व्यय – गैर–ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियां)। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का एक बड़ा अंश यह दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए उपयोग किया जाता है न कि निवेश के लिए।

Government Budget and the Economy

Primary Deficit: **We must note that the borrowing requirement of the government includes interest obligations on accumulated debt. The goal of measuring primary deficit is to focus on present fiscal imbalances.**

Gross primary deficit = Gross fiscal deficit – Net interest liabilities Net interest liabilities consist of interest payments minus interest receipts by the government on net domestic lending.

प्राथमिक घाटा: ध्यातव्य है कि सरकार की ऋण–ग्रहण आवश्यकताओं में संचित ऋण पर दायित्व शामिल होते हैं।

प्राथमिक घाटे के माप का लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रकाश डालना है।

सकल प्राथमिक घाटा = सकल राजकोषीय घाटा – निवल ब्याज दायित्व निवल ब्याज दायित्वों में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है।

Government Budget and the Economy

The government directly affects the level of equilibrium income in two specific ways – government purchases of goods and services (G) increase aggregate demand and taxes, and transfers affect the relation between income (Y) and disposable income (YD) – the income available for consumption and saving with the households. We take taxes first. We assume that the government imposes taxes that do not depend on income, called lump-sum taxes equal to T.

सरकार दो विशिष्ट विधियों से प्रत्यक्ष रूप से संतुलित आय के स्तर पर प्रभाव डालती है: सरकार द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं और सेवाओं (G) से समस्त माँग में वृद्धि होती है और करों तथा अंतरणों से आय (Y) और प्रयोज्य आय (YD)—परिवार के उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध आय (D)—का संबंध प्रभावित होता है। सर्वप्रथम हम करों को लें। हम कल्पना करते हैं कि सरकार जो कर लगाती है, वह आय पर निर्भर नहीं करता है। इसे इकमुश्त कर कहते हैं, जो T के बराबर होता है।

Government Budget and the Economy

We assume throughout the analysis that government makes a constant a-ount of transfers, — TR The consumption function is now

$$C = \bar{C} + cYD = \bar{C} + c(Y - T + \overline{TR})$$

where YD = disposable income.

हम कल्पना करते हैं कि पूरे विश्लेषण में सरकार एक नियत मात्रा में अंतरण $\overline{TR}$ करती है। अब उपभोग फलन इस प्रकार है,

$$C = \bar{C} + cYD = \bar{C} + c(Y - T + \overline{TR})$$

यहां YD = प्रयोज्य आय

Government Budget and the Economy

Changes in Government Expenditure

We consider the effects of increasing government purchases (G) keeping taxes constant. When G exceeds T, the government runs a deficit. Because G is a component of aggregate spending, planned aggregate expenditure will increase. The aggregate demand schedule shifts up to AD′. At the initial level of output, demand exceeds supply and firms expand production. The new equilibrium is at E′.

सरकारी व्यय में परिवर्तन

अब हम करों को स्थिर रखकर सरकारी खरीद (G) में वृद्धि के प्रभावों पर विचार करें। जब T अर्थात इकमुश्त कर से G अर्थात सरकारी खरीद अधिक होती है, तो सरकार घाटे का वहन करती है। क्योंकि ळ समस्त व्यय का घटक है। योजनाबद्ध समस्त व्यय में वृद्धि होगी। समस्त माँग अनुसूची में ऊपर की ओर AD' तक शिफ्ट होती है। निर्गत के प्रारंभिक स्तर पर माँग, पूर्ति से अधिक होती है और फर्म उत्पादन में विस्तार करती है। नया संतुलन E' पर स्थापित होता है।

Government Budget and the Economy

Changes in Taxes

We find that a cut in taxes increases disposable income (Y – T) at each level of income. This shifts the aggregate expenditure schedule upwards by a fraction c of the decrease in taxes.

करों में परिवर्तन हम पाते हैं कि आय के प्रत्येक स्तर पर करों में कटौती से प्रयोज्य आय (Y–T) में वृद्धि होती है। फलस्वरूप समस्त व्यय अनुसूची में ऊपर की ओर शिफ्ट होता है जो, करों में कमी का अंश c होता है।

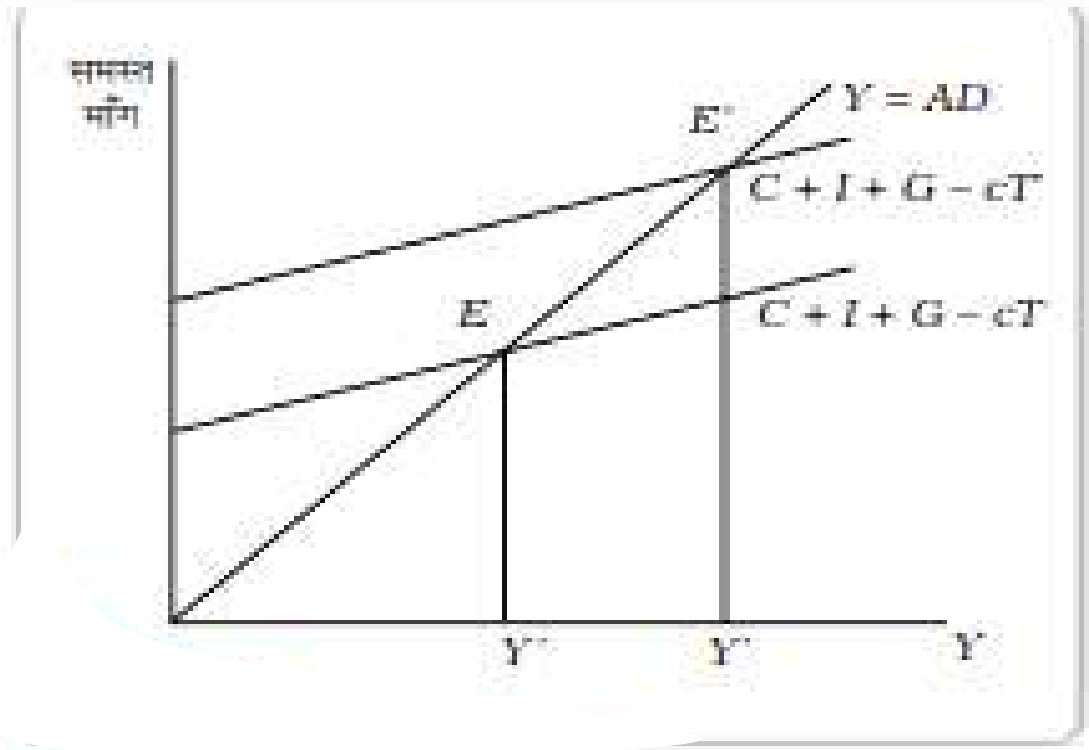

करों में कटौती का प्रभाव

Government Budget and the Economy

Because a tax cut (increase) will cause an increase (reduction) in consumption and output, the tax multiplier is a negative multiplier . Comparing equation (5.6) and (5.8), we find that the tax multiplier is smaller in absolute value compared to the government multiplier.

करों में कटौती (वृद्धि) से उपभोग और निर्गत में वृद्धि (कमी) होती है क्योंकि कर गुणक एक ऋणात्मक गुणक होता है। समीकरण 5.6 और 5.8 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि सरकार के व्यय गुणक की तुलना में कर गुणक का निरपेक्ष मूल्य अपेक्षाकृत अल्प होता है।

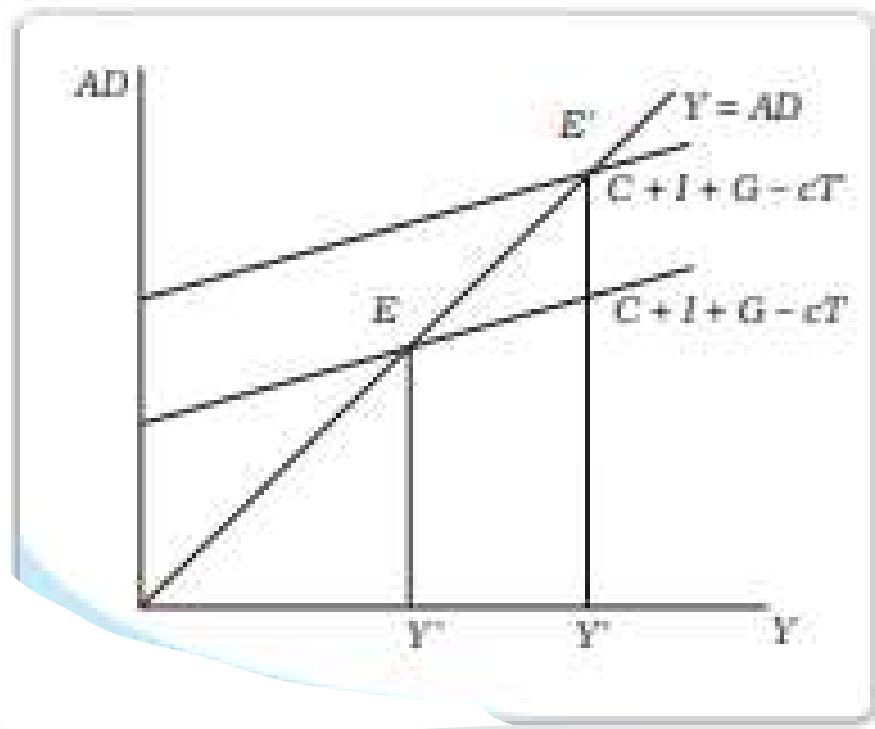

Effect of a Reduction in Taxes

Government Budget and the Economy

Case of Proportional Taxes: A more realistic assumption would be that the government collects a constant fraction, t, of income in the form of taxes so that T = tY. The consumption function with proportional taxes is given by

$$C = \bar{C} + c(Y - tY + \bar{TR}) = \bar{C} + c(1 - t)Y + c\bar{TR}$$

आनुपातिक करों की स्थिति: अधिक यथार्थ मान्यता यह होगी कि सरकार एक नियत भिन्न t के रूप में करों से आय संग्रह करती है ताकि T = tY हो। आनुपातिक करों के साथ उपभोग फलन निम्नांकित है:

$$C = \bar{C} + c(Y - tY + \bar{TR}) = \bar{C} + c(1 - t)Y + c\bar{TR}$$

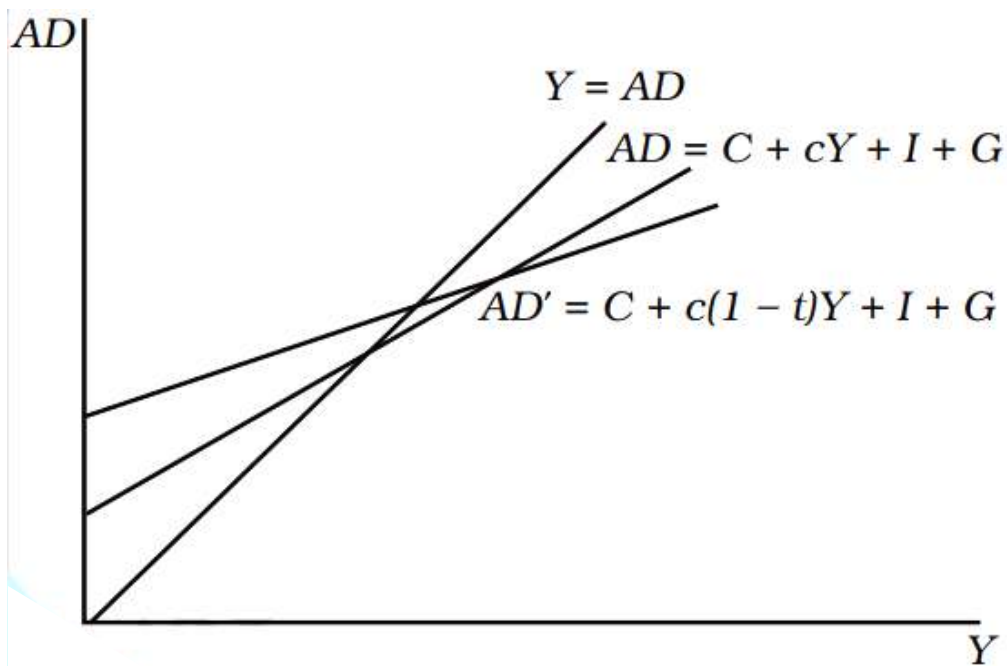

Government Budget and the Economy

Where $\bar{A}$ = autonomous expenditure and equals $\bar{C} + c\bar{TR} + I + G$. Income determination condition in the product market is, $Y = AD$, which can be written as

$$Y = \bar{A} + c(1 - t)Y \qquad (5.16)$$

Solving for the equilibrium level of income

$$Y^* = \frac{1}{1 - c(1 - t)}\bar{A} \qquad (5.17)$$

so that the multiplier is given by

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{A}} = \frac{1}{1 - c(1 - t)} \qquad (5.18)$$

Comparing this with the value of the multiplier with lump-sum taxes case, we find that the value has become smaller. When income rose as a result of an increase in government spending in the case of lump-sum taxes.

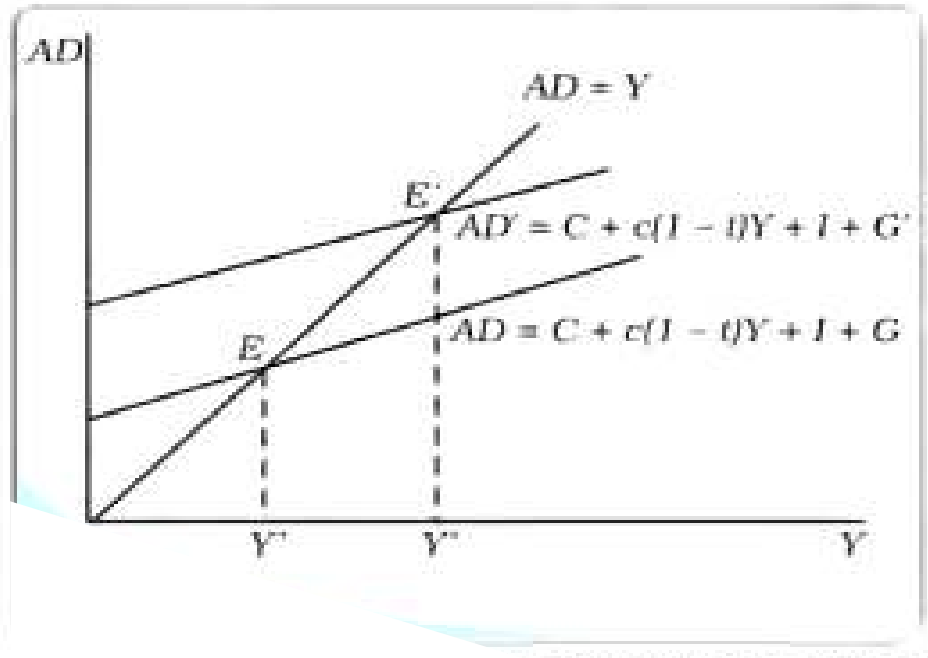

Increase in Government Expenditure (with proportional taxes)

जहाँ $\bar{A}$ = स्वायत्त व्यय है और $\bar{C} + c\bar{TR} + I + G$ के बराबर होता है। उत्पाद बाजार में आय निर्धारण की शर्त $Y = AD$ होती है, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$Y = \bar{A} + c(1-t)Y \qquad (5.16)$$

आय के संतुलन स्तर के लिए हल करने पर

$$Y = \frac{1}{1-c(1-t)}\bar{A} \qquad (5.17)$$

ताकि गुणक निम्नांकित हो

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{A}} = \frac{1}{1-c(1-t)} \qquad (5.18)$$

इकमुश्त कर की स्थिति में गुणक के मूल्य से इसकी तुलना करने पर हमें अल्प मूल्य प्राप्त होता है। इकमुश्त कर की स्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय में वृद्धि की c गुणा वृद्धि होती है। आनुपातिक कर के साथ उपभोग में कम वृद्धि होती है, $(c - ct = c(1-t))$ गुणा आय में वृद्धि होती है।

G में परिवर्तन के लिए अब गुणक निम्नांकित होगा

$$\Delta Y = \Delta \bar{G} + c(1-t)\Delta Y$$

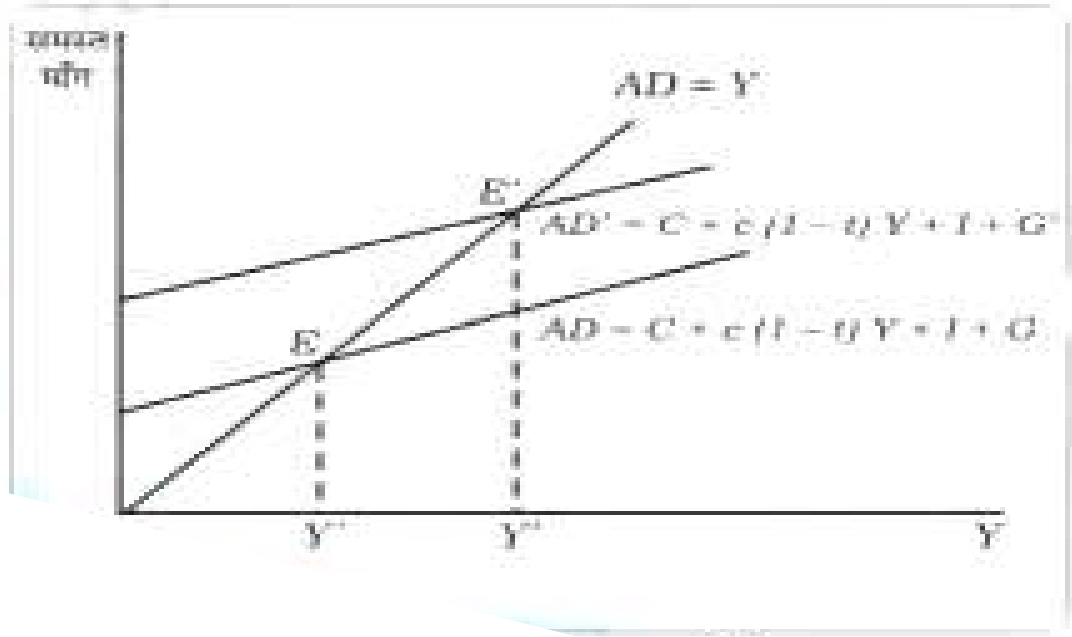

सरकारी व्यय में वृद्धि (आनुपातिक करों से)

Government Budget and the Economy

The proportional income tax, thus, acts as an automatic stabiliser – a shock absorber because it makes disposable income, and thus consumer spending, less sensitive to fluctuations in GDP. When GDP rises, disposable income also rises but by less than the rise in GDP because a part of it is siphoned off as taxes. This helps limit the upward fluctuation in consumption spending.

अत: आनुपातिक आय कर एक स्वत:स्थिरक अर्थात आघात अवशोषक की प्रकृति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इससे सकल घरेलू उत्पाद में उच्चावचन के प्रति प्रयोज्य आय और उपभोक्ता का व्यय कम संवेदनशील होता है। जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है तो प्रयोज्य आय भी बढ़ती है किंतु सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से कम, क्योंकि इसका एक अंश करों के रूप में निकल जाता है। इससे उपभोग व्यय में उपरिमुख उच्चावचन को सीमित करने में मदद मिलती है।

Government Budget and the Economy

During a recession when GDP falls, disposable income falls less sharply, and consumption does not drop as much as it otherwise would have fallen had the tax liability been fixed. This reduces the fall in aggregate demand and stabilises the economy.

अमंदी के दौरान जब सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है, तो प्रयोज्य आय कम तेज़ी से गिरती है और उपभोग में उतनी गिरावट नहीं आती है जितनी कर दायित्व नियत होने की स्थिति में आनी चाहिए। इससे समस्त माँग में कमी आती है और अर्थव्यवस्था स्थिरीकरण की स्थिति में आ जाती है।

This deliberate action to stabilise the economy is often referred to as discretionary fiscal policy to distinguish it from the inherent automatic stabilising properties of the fiscal system. As discussed earlier, proportional taxes help to stabilise the economy against upward and downward movements. Welfare transfers also help to stabilise income.

राजकोषीय प्रणाली के अंतर्निहित स्वत: स्थिरक अभिलक्षणों से अलग करने के लिए इसे स्वनिर्णयगत राजकोषीय नीति कहा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की एक सुविचारित कार्रवाई है। जैसाकि पहले चर्चा की गई है कि आनुपातिक करों से अर्थव्यवस्था को उर्ध्वगामी और अधोगामी संचलन के विरुद्ध स्थिरीकरण की स्थिति में लाने में मदद मिलती है। कल्याण अंतरणों से भी आय स्थिरीकरण में मदद मिलती है।

Government Budget and the Economy

During boom years, when employment is high, tax receipts collected to finance such expenditure increase exerting a stabilising pressure on high consumption spending; conversely, during a slump, these welfare payments help sustain consumption. Further, even the private sector has built-in stabilisers. Corporations maintain their dividends in the face of a change in income in the short run and households try to maintain their previous living standards.

तेज़ी के दौरान जब रोज़गार अधिक होता है, उपभोग व्यय के ऊँचे स्तर पर स्थिरीकरण दबाव बनाने वाले अंतरण अदायगी के लिए वित्त प्रबंधन हेतु संग्रहित कर प्राप्तियों में वृद्धि होती है; विलोमत: चरम मंदी के दौरान इन कल्याणगत अदायगियों से उपभोग धारित रखने में मदद मिलती है। आगे, निजी क्षेत्र में भी आभ्यंतरिक स्थिरक होते हैं। अल्पकाल में आय में परिवर्तन के बावजूद निगम अपने लाभांश को कायम रखते हैं और परिवार अपने पूर्व जीवन-स्तर को बनाय रखने का प्रयास करता है।

Government Budget and the Economy

All these work as shock absorbers without the need for any decision-maker to take action. That is, they work automatically. The built-in stabilisers, however, reduce only part of the fluctuation in the economy, the rest must be taken care of by deliberate policy initiative.

य सभी किसी निर्णयकर्ता के द्वारा किसी भी कार्रवाई करने की आवश्यकता के बगैर आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात य स्वत: कार्य करते हैं। किंतु आभ्यंतरिक स्थिरक से अर्थव्यवस्था में उच्चावचन को एक अंश मात्र की ही कमी होती है, शेष के लिए सुविचारित नीतिगत पहल किया जाना चाहिए।

Government Budget and the Economy

Transfers: We suppose that instead of raising government spending in goods and services, government increases transfer payments, $\bar{TR}$. Autonomous spending, $\bar{A}$, will increase by $c\Delta\bar{TR}$, so output will rise by less than the amount by which it increases when government expenditure increases because a part of any increase in transfer payments is saved. Using the method used earlier for deriving the government expenditure multipier and the taxation multiplier the change in equilibrium income for a change in transfers is given by

$$\Delta Y = \frac{c}{1-c}\Delta TR$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TR} = \frac{c}{1-c}$$

अंतरण: हम कल्पना करते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि के स्थान पर सरकार अंतरण अदायगी कुल राजस्व ($\bar{TR}$) में वृद्धि करती है। स्वायत्त व्यय $\bar{A}$, में $c\Delta\bar{TR}$ की वृद्धि होगी, अत: निर्गत में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि सरकारी व्यय में वृद्धि की मात्रा से कम होगी क्योंकि अंतरण अदायगी में किसी भी प्रकार की वृद्धि के एक अंश की बचत कर ली जाती है। अंतरण में परिवर्तन के लिए संतुलन आय में परिवर्तन निम्नवत् होगा। उसी विधि का प्रयोग कर जो पहले सरकारी व्यय गुणाक तथा कराधान गुणाक को ज्ञात करने में प्रयोग की गई है, हस्तातरणों के लिये संतुलन आय में परिवर्तन को ऐसे ज्ञात किया जा सकता है:

$$\Delta Y = \frac{c}{1-c}\Delta TR$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TR} = \frac{c}{1-c}$$

Government Budget and the Economy

Debt

Budgetary deficits must be financed by either taxation, borrowing or printing money. Governments have mostly relied on borrowing, giving rise to what is called government debt. The concepts of deficits and debt are closely related. Deficits can be thought of as a flow which add to the stock of debt. If the government continues to borrow year after year, it leads to the accumulation of debt and the government has to pay more and more by way of interest. These interest payments themselves contribute to the debt.

ऋण

बजटीय घाटे के लिए वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छापकर किया जाना चाहिए। सरकार प्रायः ऋण-ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। घाटे और ऋण की संकल्पनाओं में निकट संबंध होता है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है, जिससे ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है। यदि सरकार का ऋण-ग्रहण एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष भी जारी रहता है, तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक-से-अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस ब्याज अदायगी से ऋण की मात्रा में स्वयं का योगदान होता है।

Government Budget and the Economy

Perspectives on the Appropriate Amount of Government Debt: There are two interlinked aspects of the issue. One is whether government debt is a burden and two, the issue of financing the debt. The burden of debt must be discussed keeping in mind that what is true of one small trader's debt may not be true for the government's debt, and one must deal with the 'whole' differently from the 'part'. Unlike any one trader, the government can raise resources through taxation and printing money.

सरकारी ऋण की समुचित मात्रा का प्ररिप्रेक्ष्य: इस विषय के दो अंतसंबंधित पहलू हैं। प्रथम, क्या सरकारी ऋण एक बोझ होता है और द्वितीय, ऋण के लिए वित्तीयन संबंधी विचार। ऋण बोझ की चर्चा करते समय यह ध्यान रहे कि सरकारी ऋण छोटे व्यापारी के ऋण के जैसा नहीं होता। अत: हमें समस्त रूप से विचार करना चाहिए न कि 'आंशिक' रूप से। किसी व्यापारी के विपरीत सरकार करारोपण के द्वारा और नोट छापकर संसाधनों में वृद्धि कर सकती है।

Government Budget and the Economy

By borrowing, the government transfers the burden of reduced consumption on future generations. This is because it borrows by issuing bonds to the people living at present but may decide to pay off the bonds some twenty years later by raising taxes. These may be levied on the young population that have just entered the work force, whose disposable income will go down and hence consumption.

उधार लेकर सरकार घटे हुए बोझ को स्थानांतरित करती है आने वाली पीढ़ियों पर खपत। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जारी करके उधार लेता है वर्तमान में रहने वाले लोगों के लिए बांड, लेकिन बांड का भुगतान करने का निर्णय ले सकते हैं कुछ साल बाद कर बढ़ाकर। ये युवा पर लगाया जा सकता है जनसंख्या जो अभी-अभी कार्यबल में प्रवेश की है, जिनकी डिस्पोजेबल आय नीचे जाना होगा और इसलिए खपत होगी।

the consumer will be concerned about future generations because they are the children and grandchildren of the present generation and the family which is the relevant decision making unit, continues living. They would increase savings now, which will fully offset the increased government dissaving so that national savings do not change. This view is called Ricardian equivalence after one of the greatest nineteenth century economists, David Ricardo, who first argued that in the face of high deficits, people

उपभोक्ता भविष्य की पीढ़ियों के बारे में चिंतित होंगे क्योंकि वे वर्तमान पीढ़ी के बच्चे और पोते हैं और परिवार जो कि निर्णय लेने वाली इकाई है, जीवित रहता है। वे अब बचत बढ़ाएंगे, जो कि बढ़ी हुई सरकार को पूरी तरह से नष्ट कर देगा ताकि राष्ट्रीय बचत में बदलाव न हो। उन्नीसवीं सदी के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक डेविड रिकार्डो के बाद इस दृश्य को रिकार्डियन तुल्यता कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार तर्क दिया कि उच्च घाटे के कारण लोग अधिक बचत करते हैं।

Government Budget and the Economy

It is called ‘equivalence’ because it argues that taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure.

इसे 'तुल्यता' कहा जाता है क्योंकि यह तर्क देता है कि कराधान और उधार वित्तपोषण के बराबर साधन हैं खर्च।

Government Budget and the Economy

It is called ‘equivalence’ because it argues that taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure.

इसे 'तुल्यता' कहा जाता है क्योंकि यह तर्क देता है कि कराधान और उधार वित्तपोषण के बराबर साधन हैं खर्च।

Government Budget and the Economy

Other Perspectives on Deficits and Debt : One of the main criticisms of deficits is that they are inflationary. This is because when government increases spending or cuts taxes, aggregate demand increases. Firms may not be able to produce higher quantities that are being demanded at the ongoing prices. Prices will, therefore, have to rise. However, if there ar e unutilised resources, output is held back by lack of demand. A high fiscal deficit is accompanied by higher demand and greater output and, therefore, need not be inflationary.

डेफिसिट्स और डेट पर अन्य परिप्रेक्ष्य: घाटे की मुख्य आलोचना में से एक यह है कि वे मुद्रास्फीति हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सरकार करों में वृद्धि या कटौती करती है, तो कुल मांग बढ़ जाती है। फर्म अधिक मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो कि चल रही कीमतों पर मांग की जा रही है। इसलिए, कीमतों में वृद्धि होगी। हालाँकि, यदि कोई ई-अनटूट किए गए संसाधन हैं, तो आउटपुट माँग की कमी के कारण वापस रखा जाता है। एक उच्च राजकोषीय घाटा उच्च मांग और अधिक उत्पादन के साथ है और इसलिए, मुद्रास्फीति की आवश्यकता नहीं है।

Government Budget and the Economy

Deficit Reduction: **Government deficit can be reduced by an increase in taxes or reduction in expenditure. In India, the government has been trying to increase tax revenue with greater reliance on direct taxes (indirect taxes are regressive in nature – they impact all income groups equally). There has also been an attempt to raise receipts through the sale of shares in PSUs. However, the major thrust has been towards reduction in government expenditure. This could be achieved through making government activities more efficient through better planning of programmes and better administration.**

घाटे में कटौती: करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा करती है (अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होता है और इनका प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ता है)। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का भी एक प्रयास किया गया है। किंतु सरकारी व्यय में कटौती पर विशेष बल दिया गया है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासनों के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है।

Government Budget and the Economy

A recent study7 by the Planning Commission has estimated that to transfer Re1 to the poor, government spends Rs 3.65 in the form of food subsidy, showing that cash transfers would lead to increase in welfare. The other way is to change the scope of the government by withdrawing from some of the areas where it operated before. Cutting back government programmes in vital areas like agriculture, education, health, poverty alleviation, etc. would adversely affect the economy. Governments in many countries run huge deficits forcing them to eventually put in place self-imposed constraints of not increasing expenditure over pre-determined levels (Box 5.2 gives the main features of the FRBMA in India).

योजना आयोग के द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन 7 में यह आकलन किया गया है कि गरीबों तक 1 रु॰ का लाभ पहुँचाने के लिए सरकार खाद्य उपदान के रूप में 3.65 रु॰ व्यय करती है। यह व्यय सरकार इस उद्देश्य से करती है कि नकद राशि के अंतरण से लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। सरकार के कार्यक्षेत्र को बदलने का दूसरा तरीका यह है कि सरकार जिन क्षेत्रों में कार्य करती रही है, उनमें से कुछ क्षेत्र निकाल दिए जाएँ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अनेक देशों में सरकार अत्यधिक घाटे का वहन करती है। पूर्व निर्धारित स्तरों पर व्यय में वृद्धि नहीं करने के लिए सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करती है। (बॉक्स 5.2 में भारत में एफ.आर.बी.एम.ए. की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन है)।

Government Budget and the Economy

1. Public goods, as distinct from private goods, are collectively consumed. Two important features of public goods are – they are non-rivalrous in that one person can increase her satisfaction from the good without reducing that obtained by others and they are non-excludable, and there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefits of the good. These make it difficult to collect fees for their use and private enterprise will in general not provide these goods. Hence, they must be provided by the government.

1. सार्वजनिक वस्तुओं का निजी वस्तुओं से अलग सामूहिक उपभोग होता है। सार्वजनिक वस्तुओं की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं—य अप्रतिस्पर्धी होती हैं अर्थात एक व्यक्ति दूसरे की संतुष्टि में कमी किए बगैर अपनी संतुष्टि में वृद्धि कर सकता है तथा वे सार्वजनिक वस्तुएँ अवज्य होती हैं अर्थात किसी को इन वस्तुओं का लाभ उठाने से वर्जित करने का कोई संभव तरीका नहीं है। इससे इनके उपयोग का शुल्क संग्रह करना कठिन होता है तथा निजी उद्यम आमतौर पर एसी वस्तुओं को मुहैया नहीं कराते हैं। अत: सरकार ही सार्वजनिक वस्तुएँ प्रदान करती है।

2. The three functions of allocation, redistribution and stabilisation operate through the expenditure and receipts of the government.

3. The budget, which gives a statement of the receipts and expenditure of the government, is divided into the revenue budget and capital budget to distinguish between current financial needs and investment in the country's capital stock.

2. य तीन फलन आवंटन, पुनर्वितरण और स्थिरीकरण इन तीनों के कार्यों का संचालन सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों के माध्यम से होता है।

3. बजट, जो सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है, को देश के पूंजीगत स्टॉक में मौजूदा वित्तीय जरूरतों और निवेश के बीच अंतर करने के लिए राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में विभाजित किया जाता है।

4. The growth of revenue deficit as a percentage of fiscal deficit points to a deterioration in the quality of government expenditure involving lower capital formation.

5. Proportional taxes reduce the autonomous expenditure multiplier because taxes reduce the marginal propensity to consume out of income.

6. Public debt is burdensome if it reduces future growth in output.

4. राजकोषीय घाटे के प्रतिशत में राजस्व घाटे की वृद्धि से निम्न पूँजी निर्माण सहित सरकारी व्यय की प्रकृति में गिरावट प्रदर्शित होती है।

5. आनुपातिक करों से स्वायत्त व्यय गुणक कम होता है क्योंकि करों के बाद शेष आय में से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी आ जाती है।

6. यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि प्रभावित होती है, तो यह एक प्रकार का बोझ है।

Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA)

In a multi-party parliamentary system, electoral concerns play an important role in determining expenditure policies. A legislative provision, it is argued, that is applicable to all governments – present and future – is likely to be effective in keeping deficits under control. The enactment of the FRBMA, in August 2003, marked a turning point in fiscal reforms, binding the government through an institutional framework to pursue a prudent fiscal policy.

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफ.आर.बी. एम.ए.)

बहुदलीय संसदीय प्रणाली में व्यय संबंधी नीतियों के निर्धारण में निर्वाचकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह तर्क दिया जाता है कि विधायो प्रावधान जो सरकार के वर्तमान और भविष्य सब पर लागू होता है, घाटों को नियंत्रित करने में प्रभावकारी होता है। अगस्त, 2003 में एफ.आर. बी.एम.ए. का अधिनियमन वित्तीय सुधार और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुसरण करने के लिए संस्थागत ढाँचे के माध्यम से सरकार को बाधित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

Government Budget and the Economy

The central government must ensure intergenerational equity and long-term macro-economic stability by achieving sufficient revenue surplus, removing fiscal obstacles to monetary policy and effective debt management by limiting deficits and borrowing. The rules under the Act were notified with effect from July, 2004.

केंद्र सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि अंतर्पीढ़ीय समता हो और पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति से दीर्घकालिक समष्टि-अर्थशास्त्रीय स्थायित्व प्राप्त हो। मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए और घाटे तथा ऋण-ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंध हो। इस अधिनियम के नियमों को जुलाई, 2004 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया।

Government Budget and the Economy

Main Features

1. The Act mandates the central government to take appropriate measures to reduce fiscal deficit to not more than 3 percent of GDP and to eliminate the revenue deficit by March 31, 20098 and thereafter build up adequate revenue surplus.

मुख्य विशेषताएँ

1. यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक और कमी करने के समुचित उपाय करने का आदेश देता है, जिससे 31 मार्च 20098 तक का राजस्व घाटे को दूर किया जाए और उसके बाद पर्याप्त राजस्व आधिक्य का निर्माण हो।

2. It requires the reduction in fiscal deficit by 0.3 per cent of GDP each year and the revenue deficit by 0.5 per cent. If this is not achieved through tax revenues, the necessary adjustment has to come from a reduction in expenditure.

3. The actual deficits may exceed the targets specified only on grounds of national security or natural calamity or such other exceptional grounds as the central government may specify

2. इसमें प्रत्यक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा में कटौती और 0.5 प्रतिशत राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बतलाई गई है। इसकी प्राप्ति यदि कर राजस्व से नहीं होती है, तो व्यय में कटौती से आवश्यक समंजन होना चाहिए।

3. निर्धारित लक्ष्य से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के आधार पर अथवा अन्य एसी आपवादिक स्थितियों, जिसे केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है, के आधार पर ही हो सकती है।

4. The central government shall not borrow from the Reserve Bank of India except by way of advances to meet temporary excess of cash disbursements over cash receipts.

5. The Reserve Bank of India must not subscribe to the primary issues of central government securities from the year 2006-07.

6. Measures to be taken to ensure greater transparency in fiscal operations.

4. केंद्र सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से नकद प्राप्तियों के ऊपर नकद प्रतिपूर्तियों के अस्थायो आधिक्य की पूर्ति के लिए अग्रिम के अलावे अन्य किसी भी प्रकार का ऋण-ग्रहण नहीं करेगी।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष 2006-07 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा।

6. वित्तीय संचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किया जाना चाहिए।

7. The central government to lay before both Houses of Parliament three statements – Medium-term Fiscal Policy Statement, The Fiscal Policy Strategy Statement, The Macroeconomic Framework Statement along with the Annual Financial Statement.

7. केंद्र सरकार को संसद से दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ तीन विवरण– मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय कार्यनीति संबंधी विवरण और समष्टि अर्थशास्त्रीय ढाँचागत विवरण प्रस्तुत करना होगा।

Government Budget and the Economy

FRBM Review Committee

In the last thirteen years since the FRBM act was enacted, the Indian economy has graduated to a middle income country. At the time of enactment of the FRBM, there was a general thinking that fiscal rules were better than discretion. However, since then the advanced countries have moved away from this but in India, the government has affirmed its faith in the fiscal policy principles set out in the FRBM.

FRBM समीक्षा समिति

विगत तरह वर्षो में जबसे FRBM अधिनियम पारित किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्य आय वाला देश हो गयो है। FRBM के पारित होने के समय यह सामान्य धारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से बेहतर है। लेकिन तब से विकसित राष्ट इस धारणा से आगे निकल गय हैं लेकिन भारत में, सरकार ने FRBM में निहित राजकोषीय सिद्धातों में अपना विश्वास सत्य घोषित कर दिया है।

Government Budget and the Economy

Therefore, there is support for retaining the basic operational framework designed in 2003 but to revamp it to incorporate the changing scenario in India and also with an eye for the future path of growth – the task that has been handed to the FRBM Review Committee.

इसलिय 2003 में स्थापित संक्रियात्मक ढाँचें को बनाय रखने के लिय समर्थन प्राप्त है और इसे भारत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना और भविष्य में विकास पथ को भी ध्यान में रखना यह वह कायं है जो FRBM समीक्षा समिति को दिया गया है।

GST: One Nation, One Tax, One Market

Goods and Service Tax (GST) is the single comprehensive indirect tax, operational from 1 July 2017, on supply of goods and services, right from the manufacturer/ service provider to the consumer. It is a destination based consumption tax with facility of Input Tax Credit in the supply chain. It is applicable throughout the country with one rate for one type of goods/service.

वस्तु एवं सेवाकर–एक राष्ट, एक कर, एक बाजार

जुलाई 2017 से लागू किया गया, वस्तु एवं सेवाकर, उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह गंतव्य आधाारित उपभोग कर है जिस पर पूर्ति श्रृंखला में आगत जमा की सुविधा प्राप्त है। यह एक ही प्रकार की वस्तुओं/सेवाओं पर एक ही दर वाला पूरे भारत में लागू कर है।

Government Budget and the Economy

It has amalgamated a large number of Central and State taxes and cesses. It has replaced large number of taxes on goods and services levied on production/ sale of goods or provision of service.

इससे बहुत जड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राज्यकीय करों और उपकरों को मिला लिया है। इसने वस्तुओं और सेवाओं पर करों को जो वस्तुओं के उत्पादन/बिक्री अथवा सेवाओं के प्रदान करने पर लगाय जाते थे, प्रतिस्थापित कर दिया है।

Credit (ITC). The total value included taxes paid on intermediate goods/services. This amounted to cascading of tax. Under GST, the tax is discharged at every stage of supply and the credit of tax paid at the previous stage is available for set off at the next stage of supply of goods and/or services. It is thus effectively a tax on value addition at each stage of supply. In view of our large and fast growing economy, it addresses to establish parity in taxation across the country, and extend principles of 'value- added taxation' to all goods and services.

क्रेडिट (ITC)। कुल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं / सेवाओं पर भुगतान किए गए कर शामिल थे। यह कर की कैस्केडिंग की राशि है। जीएसटी के तहत, कर को आपूर्ति के प्रत्येक चरण में छुट्टी दे दी जाती है और पिछले चरण में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट माल और / या सेवाओं की आपूर्ति के अगले चरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह प्रभावी रूप से आपूर्ति के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर कर है। हमारी बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, यह देश भर में कराधान में समानता स्थापित करने और सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए ation मूल्य वर्धित कराधान 'के सिद्धांतों का विस्तार करने के लिए संबोधित करता है।

Government Budget and the Economy

It has replaced various types of taxes/cesses, levied by the Central and State/UT Governments. Some of the major taxes that were levied by Centre were Central Excise Duty, Service Tax, Central Sales Tax, Cesses like KKC and SBC. The major State taxes were VAT/Sales Tax, Entry Tax, Luxury Tax, Octroi, Entertainment Tax, Taxes on Advertisements, Taxes on Lottery /Betting/ Gambling, State Cesses on goods etc. These have been subsumed in GST.

इसने केन्द्र/राज्य/ केन्द्रशासित प्रदशों के द्वारा लगाय गय विभिन्न प्रकार के करों/उपकरों को प्रतिस्थापित कर दिया है। केन्द्र द्वारा लगाय गय कुछ कर केन्द्रीय उत्पादन कर, सेवाकर, केन्द्रीय बिक्री कर, और कृषि कल्याण कर, स्वच्छ भारतकर उपकर थे। राज्य के प्रमुखकर, वाट/सेल्सटैक्स, प्रवेशकर, विलासिता कर, चुँगी, मनोरंजन कर विज्ञापनों पर कर, लौटरी/बैंटिग/जुआकर, वस्तुओं पर राज्योय कर आदि थे। य सब वस्तु एवं सेवा में समाहित हो गय हैं।

Government Budget and the Economy

Five petroleum products have been kept out of GST for the time being but with passage of time, they will get subsumed in GST. State Governments will continue to levy VAT on alcoholic liquor for human consumption. Tobacco and tobacco products will attract both GST and Central Excise Duty. Under GST, there are 6 (six) standard rates applied i.e. 0%, 3%,5%, 12%,18% and 28% on supply of all goods and/or services across the country.

वर्तमान में पैट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है, लेकिन समय बीतने के साथ इन्हें भी वस्तु एवं सेवाकर में समाहित कर दिया जायगा। मानव उपयोग के लिय मादक पेयों पर राज्य सरकारें वस्तु और सेवाकर लगाती रहेगी। तम्बाकू तथा तम्बाकू पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। वस्तु एवं सेवाकर के अर्न्तगत पूरे देश में वस्तुओं और अथवा वस्तुओं पर 6 मानक दरें जैसे, 0% 3%, 5%, 12%, 18% तथा 28 % लागू होंगी।

Government Budget and the Economy

GST is the biggest tax reform in the country since independence and was rolled out on the mid-night of 30 June/1 July, 2017 during a special midnight session of the Parliament. The 101th Constitution Amendment Act received assent of the President of India on 8 September, 2016. The amendment introduced Article 246A in the Constitution cross empowering Parliament and Legislatures of States to make laws with reference to Goods and Service Tax imposed by the Union and the States. Thereafter CGST Act, UTGST Act and SGST Acts were enacted for GST. GST has simplified the multiplicity of taxes on goods and services.

स्वतंत्रता के पश्चात्, वस्तु एवं सेवाकर, देश में सबसे बड़ा कर सुधार है जो 30 जून/ 1 जुलाई 2017 की अर्थरात्रि को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया। ग्यारवें संविधान संशोधन अधि नियम को 8 सितम्बर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस संशोधन से संविधान में धारा 246 । शामिल हुआ जिसने संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं का वस्तुओं एवं सेवाकर संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। इसके पश्चात् वस्तुओं सेवाकर के लिय ळैज ।बजए न्ळैज ।बज और ळैज ।बजे पारित किय गय। अधिनियम, प्रक्रियाऐं और पूरे भारत में करों की दरों का मानकीकरण हो गया है।

It will also result into higher economic growth as GDP is expected to rise by about 2%. Compliance will also be easier as all tax payment related services like registration, returns, payments are available online through a common portal www.gst.gov.in. It has expanded the tax base, introduced higher transparency in the taxation system, reduced human interface between Taxpayer and Government and is furthering ease of doing business.

इससे आर्थिक विकास बढ़ग क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च) में कोई 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कर अनुपालन भी अधिक होगा क्योंकि कर अदायगी संबंधी सेवाऐं जैसे पंजीकरण, रिटर्न भरना, कर अदायगी, सभी एक सामान्य पोर्टल ,ण्हेजण्हवअण्पद पर ऑन-लाइन उपलब्ध हैं। इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया है, कर व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता ला दी है, सरकार और करदाताओं के बीच मानव अंर्तप्रदेश को कम कर दिया है और व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ावा दे रही है।